बिहार में सड़कों का निर्माण निजी भागीदारी से : नितिन

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। हैम (हाइब्रिड एन्युटी मॉडल) मोड से राज्य में गंगा पथ के अलावा राजकीय उच्च पथ (स्टेट हाईवे) का निर्माण होगा। पथ निर्माण विभाग ऐसी सड़कों की पहचान कर रहा है जिस पर गाड़ियों का अधिक दबाव है। साथ ही वहां जाम की समस्या अधिक लग रही है। जेपी गंगा पथ में दीघा से कोईलवर और मुंगेर से सबौर तक बनने वाले गंगा पथ का निर्माण इसी मोड में होगा।

मंगलवार को अपने विभागीय कक्ष में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पत्रकारों से कहा कि बिहार की आधारभूत संरचना को आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में विभाग लगातार निर्णायक कदम उठा रहा है। बजट सत्र में ही हमने घोषणा की थी कि राज्य में सड़क, पुल एवं एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के लिए एचएएम मॉडल अपनाया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार वृहद इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया और कार्य योजना एचएएम मॉडल की शुरुआत कर रहा है। यह मॉडल खास तर पर डिफर्ड पेमेंट सिस्टम पर आधारित है। इसमें परियोजना की निर्माण अवधि चार वर्षों की होती है, जबकि निर्माण के पश्चात 15 वर्षों तक उसका रखरखाव

- **हैम मॉडल में चार वर्ष में परियोजनाओं का निर्माण होगा पूरा**
- **निर्माण एजेंसी 60 फीसदी तो 40 फीसदी सरकार वहन करेगी**

संवेदक के जिम्मे होता है। चार वर्ष के निर्माण काल में सरकार द्वारा परियोजना लागत का मात्र 40 फीसदी भुगतान किया जाएगा, जबकि शेष 60 फीसदी राशि संवेदक स्वयं निवेश करेगा।

15 वर्षों तक सरकार द्वारा यह राशि ब्याज सहित संवेदक को चुकाई जाएगी। साथ ही संचालन एवं रखरखाव के लिए सरकार अलग से राशि भी देगी। यह एक प्रकार का पीपीपी मॉडल है। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि एचएएम मोड में टोल टैक्स की वसूली हो या नहीं, यह परियोजना पूरा होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। जेपी गंगा पथ में पहले टोल टैक्स वसूलने की बात चली थी, लेकिन बाद में सरकार ने खुद अपने फंड से इसका निर्माण कराया। मौके पर विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी, विशेष सचिव शीर्षत कपिल अशोक भी मौजूद थे।

विभागीय हॉल में मंगलवार को प्रेसवार्ता को संबोधित करते पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। साथ में विभाग के सचिव संदीप कमार आर पडकलकट्टी, विशेष सचिव शीर्षत